

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

दावोस में कर दिया बड़ा दावा, रूस ने एक झटके में किया खंडन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि रूस के व्लादिमीर पुतिन उनके 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। जबकि रूस का कहना है कि वह अभी भी इस निमंत्रण का अध्ययन कर रहा है। स्विट्जरलैंड के दावोस में मीडिया को ट्रंप ने बताया, 'उन्होंने आमंत्रित किया गया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। कई लोगों ने इसे स्वीकार किया है।' जब ट्रंप से गैर-लोकतांत्रिक और विवादित हस्तियों को जोड़ने पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग 'विवादास्पद' हो सकते हैं, लेकिन 'अगर मैं बोर्ड में केवल 'दूध पीते बच्चों' को रखूंगा, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा।



रूस ने क्या कहा?

दूसरी ओर, मॉस्को में पुतिन ने एक

कैबिनेट बैठक में बताया कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को इस प्रस्ताव का अध्ययन करने का आदेश दिया है।

पुतिन ने कहा, 'रूसी विदेश मंत्रालय को उन दस्तावेजों का अध्ययन करने और हमारे रणनीतिक भागीदारों के साथ परामर्श करने का जिम्मा सौंपा गया है जो हमें भेजे गए हैं। उसके बाद ही हम निमंत्रण का उत्तर दे पाएंगे।'

क्या तैयार हैं पुतिन?

पुतिन ने यह भी कहा कि रूस स्थायी सदस्यता के लिए मांगी गई 1 अरब डॉलर की राशि का भुगतान 'पिछली अमेरिकी सरकार द्वारा फ्रीज की गई रूसी संपत्ति' से कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इन संपत्तियों का उपयोग रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता होने के बाद युद्ध से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों

के पुनर्निर्माण के लिए भी किया जा सकता है।

क्या है 'बोर्ड ऑफ पीस'?

ट्रंप ने दुनिया के दर्जनों नेताओं को इस बोर्ड में स्थायी सीट के लिए 1 अरब डॉलर के अनुरोध के साथ निमंत्रण भेजा है। हालांकि, मूल रूप से इसे गाजा के पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए बनाया गया था, लेकिन बोर्ड का चार्टर इसकी भूमिका को केवल गाजा तक सीमित नहीं रखता। ऐसा लगता कि यह संयुक्त राष्ट्र के प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरना चाहता है, जिससे फ्रांस सहित अमेरिका के कुछ सहयोगी देश नाराज हैं।

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये मिलकर बना रहे इस्लामी नाटो, भारत भी चल रहा ये दांव



पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए सैन्य समझौता हुआ। इस समझौते का मतलब ये हुआ कि एक देश पर बाहरी हमला दूसरे देशों पर हमला माना जाएगा। तुर्किये भी लंबे समय से इस्लामी देशों का नेतृत्व करने की चाहत रखता है। ये तीनों देश मिलकर आने वाले समय में एक इस्लामी नाटो का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें इन तीनों देशों के हित शामिल होंगे। **इस्लामी नाटो का निर्माण-** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोकस 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' बनाने की ओर है। वहीं अमेरिका से कम हो रहे भरोसे के बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये इस्लामी नाटो बनाने के राह पर चल दिए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते से सऊदी अरब को एक परमाणु हथियार से संपन्न देश का साथ मिला वहीं पाकिस्तान को संसाधनों से समृद्ध सऊदी अरब से मदद की उम्मीद मिली। भारत पाकिस्तान के संघर्ष में हो सकता है कि सऊदी अरब सीधे सैन्य हस्तक्षेप न करे लेकिन वह पाकिस्तान की आर्थिक मदद तो कर ही सकता है। तुर्किये के भी इस संगठन में शामिल होने से अपने रक्षा उत्पादों के लिए खाड़ी देशों में बाजार भी मिल सकेगा। तुर्किये की उन्नत रक्षा तकनीक का फायदा सऊदी अरब और पाकिस्तान को भी मिलेगा। **इस्लामी नाटो के खिलाफ भारत की तैयारी-** सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये गठबंधन एक तरफ है, तो यूएई और इजरायल के साथ भारत के बढ़ते रक्षा और रणनीतिक संबंध दूसरी तरफ हैं। 19 जनवरी को, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत, यूएई और इजरायल के साथ एक नया भू-राजनीतिक गठबंधन बना रहा है ताकि पाकिस्तान और चीन के साथ उभरते तुर्किये-सऊदी अरब गठबंधन का मुकाबला किया जा सके। ये नए गठबंधन अमेरिकी और यूरोपीय शक्ति के सिकुड़ने का सीधा नतीजा हैं। यह रणनीतिक दांव अरब खाड़ी से भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा है। वहां, ग्रीस, साइप्रस और इजरायल एक आक्रामक तुर्किये के खिलाफ रणनीतिक गठबंधन को मजबूत बना रहे हैं।

35 कफ सिरप सहित 174 दवाओं के सैंपल फेल, CDSCO ने जारी की सूची हिमाचल व उत्तराखंड की सबसे ज्यादा मेडिसिन शामिल

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की ओर से जारी ड्रग अलर्ट में 35 कफ सिरप सहित 174 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरीं हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। फेल सैंपल में सबसे अधिक 51 दवाएं हिमाचल और 29 उत्तराखंड से पाई गई हैं। 174 दवाओं में से सात नकली पाई गई हैं। सीडीएससीओ के दिसंबर के ड्रग अलर्ट में दिल, कैंसर, मधुमेह, हाई बीपी, अस्थमा, संक्रमण, दर्द, सूजन, पेट के कीड़े, अनीमिया, मिर्गी, एसिडिटी, एलर्जी, सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। हर माह देशभर की ड्रग टेस्टिंग लैब में दवाओं की गुणवत्ता को परखा जाता है, जिसमें इंजेक्शन, टैबलेट, सिरप, आई ड्रॉप व कैप्सूल शामिल हैं। देशभर में हर माह हजारों दवाओं का परीक्षण होता है, जिनमें से कुछ फेल पाई जाती हैं।

प्रमुख बीमारियों की ये दवाएं हुई फेल

सोलन के फार्मा कैमिको में कीमोथैरेपी, सर्जरी या उल्टी रोकने के लिए बने इंजेक्शन ओडांस्ट्रोन एंड रानीटिडिन एचसीआइ (बैच नंबर 110525), पटना के वेस्टरलिन ड्रग्स में निर्मित सर्दी-जुकाम, नाक बहना और एलर्जी के लक्षणों से राहत दिलाने वाले सिरप हाइड्रोक्लोराइड क्लोरफिनामिन मलियट क्यूआर-कोल्ड सिरप (बैच नंबर डब्ल्यूडीएलबी012), बच्चों की सर्दी-खांसी में इस्तेमाल होने वाले पंजाब के एस्पेन लाइफसाइंस में बने कोरन-एलए जूनियर सिरप (बैच नंबर ए20497बी) का सैंपल फेल पाया गया है। गुजरात के रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल में बने मेंथल सिरप (बैच नंबर आर12जीएल2426), उत्तर प्रदेश के यूनिक्योर इंडिया में निर्मित ब्लड शुगर नियंत्रित करने में उपयोग होने वाली विल्डार्गिलिप्टिन और मेटफार्मिन टैबलेट (बैच वीएमएचटी1315), नालागढ़ के थियोन फार्मास्यूटिकल्स में निर्मित हृदय रोगों में रक्त के थक्के बनने से रोकने और स्ट्रोक व हृदयाघात के जोखिम को कम करने वाली दवा क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन टैबलेट्स (बैच जीटी250519) सहित अन्य कई बीमारियों की दवाओं के सैंपल भी फेल पाए गए हैं।



किस राज्य की कितनी दवाएं हुई फेल

हिमाचल के बड़ी, नालागढ़, सिरमौर की दवा कंपनियों में बनी दवाएं गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरी हैं। हिमाचल से 51, उत्तराखंड से 29, तमिलनाडु से 18, गुजरात से 12, हरियाणा से आठ, पंजाब से सात, महाराष्ट्र, बंगाल व राजस्थान से चार-चार दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। बिहार, कर्नाटक, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी से तीन-तीन, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दो-दो और केरल, ओडिशा, सऊदी अरब, आंध्र प्रदेश, असम व जेएंडके से एक-एक दवा का सैंपल फेल पाया गया है।

ये सात दवाएं पाई गईं नकली

सीडीएससीओ ने रिपोर्ट में सात नकली दवाओं का जिक्र किया है। हालांकि इन दवाओं के रैपर पर किसी कंपनी का नाम अंकित था, लेकिन उन कंपनियों ने उस बैच को नकारा है और अब यह मामला जांच के अधीन है। इन दवाओं में काइमोरल फोर्टे (बैच नंबर 2केयू6एल045), टेलमा-एएम 40एमजी एंड एमलोडिपाइन पांच एमजी (बैच नंबर 18240626), टेलमा-40 (बैच नंबर 18240413), टेलमा-एएम 40एमजी एंड एमलोडिपाइन पांच एमजी (बैच नंबर 05241038ए), मॉंटिना-एल टैबलेट (बैच नंबर एसपीजे 241236), पैन्टाप-डी एसआर (बैच नंबर एसपीए250021) और काइमोरल फोर्टे (बैच नंबर 2केयू6एल012) को नकली करार दिया है।

इंदौर कालानी नगर क्षेत्र की धर्मराज कॉलोनी में नगर निगम की कार्रवाई ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं

राजेश धाकड़

अवैध निर्माण हटाने पहुंचे भवन अधिकारी के पास फोन कॉल्स की भरमार, सवालों के अधूरे जवाब और जवाबों में टालमटोल—पूरी कार्रवाई पर संदेह की परतें चढ़ती दिखीं। शहर में जहां बड़े-बड़े भूमाफिया बेखौफ नजर आते हैं, वहीं गरीबों के मकानों पर पोकलेन चलाने की जल्दबाजी समझ से परे है।

धर्मराज कॉलोनी की संकरी गलियों में पोकलेन को लाने के लिए मशीन को गली-गली घुमाया गया—मानो कार्रवाई तय थी, बस जगह तलाशनी थी। आखिरकार जैसे-तैसे पोकलेन मौके तक पहुंचा और दीवारें गिरा दी गईं। यह कार्रवाई जोन क्रमांक-20 के भवन अधिकारी वैभव देवलासे के नेतृत्व में हुई। गौरतलब है कि वैभव देवलासे पूर्व में चंदन नगर बोर्ड से जुड़े एक मामले में निलंबित भी रह चुके हैं। इसके बावजूद इतनी जल्दी और इतनी संवेदनशील जगह पर कार्रवाई के लिए



पहुंचना कई सवाल खड़े करता है।

सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जिन मकानों को अवैध बताया जा रहा है, उनके पास रजिस्ट्री

मौजूद है और वर्षों से इंदौर नगर निगम को नियमित भवन कर भी जमा किया जा रहा है। ऐसे में यदि जमीन सरकारी है, तो फिर नगर निगम टैक्स

किस आधार पर ले रहा है? इस सवाल पर भवन अधिकारी स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए। कार्रवाई के दौरान मानवीय संवेदनाओं की भी अनदेखी हुई। जिस गरीब परिवार की दीवार गिराई गई, उस परिवार की महिला दोनों आंखों से दृष्टिहीन है और गर्भवती भी। बावजूद इसके, बिना वैकल्पिक व्यवस्था और बिना संवेदनशीलता दिखाए उसकी दीवार गिरा दी गई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जमीन सच में सरकारी है, तो वर्षों तक टैक्स क्यों लिया गया? और यदि अवैध निर्माण है, तो पहले बड़े अवैध कब्जों पर कार्रवाई क्यों नहीं? कॉलोनीवासियों ने इस कार्रवाई को चयनात्मक बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब सवाल साफ हैं—क्या नगर निगम के रिकॉर्ड में जमीन सरकारी है या निजी? क्या टैक्स वसूली की जवाबदेही तय होगी? और क्या कार्रवाई सिर्फ गरीबों तक ही सीमित रहेगी? इन सवालों के जवाब अब प्रशासन को देने होंगे।

गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए, इंदौर पुलिस ने की सरवटे बस स्टैंड पर बम थ्रेट मॉक ड्रिल



आदित्य शर्मा

किसी आपातकालीन परिस्थितिलावारिस(विस्फोटक सामग्री) वस्तु मिलने पर, कैसे हो सुरक्षा के मापदंड, इसको लेकर कराया जीवंत अभ्यास

इंदौर- शहर की सुरक्षा व्यवस्था तथा शहर में विभिन्न आयोजनों के साथ ही गणतंत्र दिवस को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर पुलिस द्वारा पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में शहर के महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की चैकिंग व निरीक्षण एवं आपातकालीन स्थिति में पुलिस, प्रशासन व संस्थानों की क्या सुरक्षा तैयारियां हैं इसका भी जायजा लिया जा रहा है। इसी अनुक्रम में अति.पुलिस आयुक्त (अप./मुख्या.) श्री आर. के. सिंह व पुलिस उपायुक्त (आसूचना एवं

सुरक्षा) श्री राजेश व्यास के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस की बीडीडीएस टीम द्वारा आज दिनांक 22.01.26 को सरवटे बस स्टैंड इंदौर में किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु किस प्रकार बेहतर सुरक्षा संबंधी प्रबंधन किया जाए इस संबंध में मॉक ड्रिल की गई।

इस ड्रिल में बीडीडीएस प्रभारी श्री खालिद मुशताक के निर्देशन में टीम व थाना छोटी ग्वालटोली स्टाफ ने बस स्टैंड के सुरक्षा स्टाफ को भी साथ लेकर, किसी आपातकालीन परिस्थितियों/ लावारिस (विस्फोटक सामग्री वाली) वस्तु मिलने पर किस प्रकार से कार्यवाही की जाए एवं जनता की सुरक्षा का ध्यान किस प्रकार रखा जाए आदि बातों का जीवंत अभ्यास कराया गया। साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा वहां की सुरक्षा के संबंध में वहां काम करने वाले स्टाफ और सुरक्षाकर्मी सहित आमजन से भी रूबरू हुए और उन्हें ऐसी स्थिति आ जाने पर सुरक्षा हेतु क्या करे व क्या न करे इस संबंध में समझाया।

सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत, इंदौर यातायात पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली

आदित्य शर्मा

इंदौर पुलिस कमिश्नर इंदौर ने हेलमेट जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर, की सभी से नियमों के पालन की अपील। पुलिस ने रैली के माध्यम से हमेशा हेलमेट पहनने व सड़क सुरक्षा का नियमों का ध्यान रखने का दिया संदेश

इंदौर- शहर में सुगम, सुरक्षित व सुखद यातायात हेतु, आम नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से, पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में, अति. पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री राजेश कुमार सिंह व पुलिस उपायुक्त (जोन4/ यातायात) नगरीय इंदौर श्री आनंद कलादगी के मार्गदर्शन में यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता माह 2026 के तहत नित नए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 22 जनवरी 2026 को यातायात प्रबंधन पुलिस ने हेलमेट बाइक रैली का आयोजन किया। पुलिस आयुक्त, नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह ने रैली में सम्मिलित सभी लोगों को सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा के लिए सदैव नियमों का पालन करने व दूसरों को भी सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने की अपील की। पुलिस कमिश्नर द्वारा हेलमेट जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हेलमेट बाइक रैली का नेतृत्व डीसीपी, यातायात श्री आनंद कलादगी ने किया। रैली पलासिया चौराहा से चलकर गीताभवन,



यातायात प्रबंधन पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी के साथ-साथ ट्रैफिक प्रहरी, बाईकर्स, जिम्मेदार नागरिक सम्मिलित हुए। यातायात प्रबंधन पुलिस, महानगर इंदौर की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता संदेश आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए आगामी दिनों में नित नए कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की जाएगी।

पुलिस कमिश्नर ने सड़क सुरक्षा का महत्व समझाते हुए, किया वाहन चालकों को हमेशा हेलमेट धारण सहित यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित

इंदौर- सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त, नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) श्री आर.के. सिंह एवं पुलिस उपायुक्त (यातायात/जोन4) श्री आनंद कलादगी के मार्गदर्शन में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में आज 20 जनवरी 2026 शहर के पलासिया चौराहे पर पुलिस आयुक्त, नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) श्री आर.के. सिंह, पुलिस उपायुक्त (यातायात/जोन4) श्री आनंद कलादगी की उपस्थिति में इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा वृहद हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया। इस



दौरान पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा युवा, बुजुर्ग, जरूरतमंद ऐसे वाहन चालक जिनके

पास रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दस्तावेज पूर्ण थे उन्हें हेलमेट प्रदान किए गए। ऐसे वाहन चालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर पहले चालान किया गया फिर सुरक्षा का महत्व समझाते हुए हेलमेट भी दिया।

ऐसे भी जिम्मेदार दोपहिया वाहन चालक इस अभियान में सम्मिलित हुए जो स्वेच्छा से हेलमेट लगाए मिले, पुलिस कमिश्नर व अधिकारियों द्वारा ऐसे जिम्मेदार चालकों की प्रशंसा करते हुए उन्हें सम्मान स्वरूप उपहार भी प्रदान किए गए। सड़क सुरक्षा का महत्व समझाने के लिए यातायात डिजिटल स्क्रीन पर सड़क सुरक्षा से जुड़े वीडियो दिखाए गए ताकि वाहन चालक हादसों की गंभीरता को समझें और नियमों का पालन करें। पुलिस कमिश्नर ने वाहन चालकों से यह भी कहा कि लगातार इन्दौर शहर के सुगम, सुरक्षित यातायात

व्यवस्था के लिए आमजन मानस को जागरूक करने व सड़क सुरक्षा में उनकी सहभागिता के लिए नित नए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों उद्देश्य यही है कि वाहन चालक सड़क सुरक्षा नियमों की गंभीरता को समझे व स्वेच्छा से यातायात नियमों का पालन करें। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार वाहन चालकों को आगे आना चाहिए और अन्य लोगों को भी सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना चाहिए। वाहन चालकों ने भी संकल्प लिया कि ना केवल हम यातायात नियमों का पालन करेंगे बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। वाहन चालकों ने पुलिस कमिश्नर से अपने अनुभव साझा किये। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, निरीक्षक गण सहित यातायात का स्टाफ, ट्रैफिक प्रहरी, जिम्मेदार नागरिक भी उपस्थित रहे।

आगामी बोर्ड एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, तेज आवाज में डीजे व लाउडस्पीकर बजाने वालों के विरुद्ध की जाएगी सख्त कार्यवाही

आदित्य शर्मा

इंदौर आगामी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए, इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा तेज आवाज में लाउडस्पीकर/डीजे बजाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। अतः स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बाधा न हो इसके लिए निम्न निर्देशों का पालन करें- रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर

इंदौर पुलिस कमिश्नर

जनहित सूचना | इंदौर पुलिस

आगामी बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए तेज आवाज में डीजे व लाउडस्पीकर बजाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

- रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक डीजे व लाउडस्पीकर पूर्णतः प्रतिबन्धित।
- किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु लिखित अनुमति व निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन अनिवार्य।
- स्कूल, कॉलेज व अस्पतालों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग निषिद्ध।

उल्लंघन पर डीजे/साउंड सिस्टम जप्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत करें: क्राइम वॉच

7049108283

या नजदीकी थाना

सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रहेगी।

और डीजे (DJ) के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु नियमानुसार लिखित अनुमति अनिवार्य होगी, जिसमें निर्धारित डेसिबल (ध्वनि सीमा) का पालन करना आवश्यक है। शिक्षण संस्थानों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग न करें। यहाँ किसी भी प्रकार का शोर न करें। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत, डीजे/साउंड सिस्टम आदि उपकरण तत्काल जप्त कर सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

आमजन से अपील:- पुलिस सभी नागरिकों, डीजे संचालकों और कार्यक्रमों के आयोजन कर्ताओं से अपील करती है कि वे छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सहयोग करें। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो इंदौर पुलिस के क्राइम वॉच हेल्पलाइन नंबर-7049108283 पर (या संबंधित स्थानीय थानों) सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। परीक्षाओं के दौरान स्टूडेंट्स के हितों का ध्यान रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

नितिन नबीन नहीं बनेंगे राज्यसभा सदस्य, राह रोकेगा अमित शाह-गडकरी वाला 'फॉर्मूला'?

बिहार की राजनीति, अभी राज्यसभा की खाली होने वाली पांच सीटों को लेकर काफी गर्म हो चली है। यह चर्चा, खास कर इस बात को लेकर है कि बीजेपी इस बार दो सीटों पर किसे भेजेगी? नितिन नबीन जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने तो यह चर्चा परवान चढ़ रही थी कि एक सीट पर तो वही जाएंगे। बीजेपी सूत्रों की माने तो नितिन नबीन राज्यसभा नहीं भी जा सकते हैं। और इसकी वजह भी है। इसके पहले भी कई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जो विधायक रहकर भी कई वर्ष तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। तो जानिए ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विधायक रहते राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। नितिन गडकरी भाजपा के जाने माने चेहरों में से एक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के सदस्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय कर चुके हैं। नितिन गडकरी भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाज रानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री भी रहे हैं। इससे पहले 2010-2013 तक वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बावन वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले वे इस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। नितिन गडकरी एक जनवरी 2010 से 22 जनवरी 2013 तक अध्यक्ष रहे। इस बीच वे वर्ष 2008 में वे अंतिम बार विधान परिषद चुने गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के समय वे विधान परिषद सदस्य थे। और ये वर्ष 2014 में नागपुर लोकसभा से चुनाव जीत कर आए थे। अमित शाह ने 2014 से 2020 तक



भारतीय जनता पार्टी के 10वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इस दौरान वे गुजरात के नरनपुरा विधानसभा से विधायक थे। अमित शाह विधायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर 2012 से 2017 तक बने रहे। यानि करीबन तीन साल बाद वे विधायक रह कर भी भाजपा के अध्यक्ष बने रहे। इसके अतिरिक्त, वे जुलाई 2021 से सहकारिता मंत्री भी हैं। वो 2014 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के अध्यक्ष भी रहे हैं। शाह 2017 से 2019 तक गुजरात से संसद के उच्च सदन, राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे।

महू की बेटी आकांक्षा वर्मा नेशनल फुटबॉल टीम में चयन एवं मणिपुर (असम) के लिए रवाना

महू-इंदौर- महू की बेटी आकांक्षा वर्मा पिता राजेश वर्मा नेशनल फुटबॉल टीम में चयन एवं मणिपुर (असम) के लिए रवाना पिता ने डाइवर रहते हुए अपनी बेटी को इस उपलब्धि तक पहुंचाने के लिए जी जान एक किया साथ ही बेटी ने भी पिता की उम्मीद पर खूब मेहनत कर नेशनल फुटबॉल टीम में चयनित हुई इस उपलब्धि पर जिला पंचायत सदस्य कन्हैयालाल ठाकुर, अशोक सैनी, जुगनू जादवसिंह धनावत, जीतू ठाकुर, शक्तिसिंह गोयल, विजेंद्रसिंह चौहान, गोपाल नेगी, शेरू भाई, राजेंद्र व्यास ने बधाई दी।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने मुख्य समारोह स्थल नेहरू स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा



इंदौर इंदौर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की व्यापक तैयारियां जारी हैं। मुख्य समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ध्वजारोहण करेंगे। इंदौर में यह समारोह सुबह 9 बजे से नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जायेगा। इस समारोह में परेड सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने आज अधिकारियों के दल के साथ नेहरू स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां निर्धारित समय से पूर्व कार्यक्रम की गरिमा के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर एडीएम श्री रोशन राय, अपर आयुक्त नगर निगम अभय राजनगांवकर सहित विभिन्न विभागों के

अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने तैयारियों की विभागवार समीक्षा की। बताया गया कि समारोह में विभिन्न प्लाटूनों द्वारा परेड भी प्रस्तुत की जायेगी। राज्य शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों पर आधारित 13 से अधिक नयनाभिराम झाँकियां भी विभिन्न विभागों द्वारा निकाली जायेंगी। खजराना गणेश मंदिर, जिला पंचायत, नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण, उद्योग, जेल, महिला बाल विकास, आदिम जाति कल्याण, सामाजिक न्याय, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी आदि विभागों द्वारा नयनाभिराम झाँकियां निकाली जायेंगी। समारोह स्थल पर आकर्षक साज-सज्जा की जायेगी। स्वतंत्रता सेनानियों एवं लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही

उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। समारोह में विभिन्न स्कूली विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाएंगे। इसी तरह इंदौर संभाग के बुरहानपुर में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, खरगोन में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग, बड़वानी में कौशल विकास एवं रोजगार विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल तथा खंडवा में संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मदेव भावसिंह लोधी ध्वजारोहण करेंगे। संभाग के धार, झाबुआ तथा आलीराजपुर जिले के मुख्य समारोह में संबंधित जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गये हैं।

RBI नियमों की धजियाँ उड़ाकर बैंक रिक्वरी एजेंटों की गुंडागर्दी; बीच सड़क पर महिलाओं से अभद्रता कर छिनी कार

इंदौर। शहर के कुंदन नगर क्षेत्र में यस बैंक (Yes Bank) के रिक्वरी एजेंटों द्वारा मानवता और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों को ताक पर रखकर सर्राह गुंडागर्दी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बैंक एजेंटों ने न केवल उनके साथ धोखाधड़ी की, बल्कि बीच रास्ते में परिवार और महिलाओं के साथ मारपीट व अभद्रता करते हुए जबरन वाहन लूट लिया।

क्या है पूरा मामला ?

कुंदन नगर निवासी किशोर पंवार ने 3 सितंबर 2023 को सपना संगीता स्थित जैन कार बाजार से एक अर्टिगा कार (MP 09 WM 1427) खरीदी थी। 10.50 लाख रुपये की इस कार के लिए उन्होंने 3.50 लाख रुपये डाउन पेमेंट दिया था और शेष राशि यस बैंक से फाइनेंस कराई थी। जिसकी 19,510 रुपये की मासिक किस्त हर महीने की 15 तारीख को नियत थी। पीड़ित के अनुसार, उन्होंने लगातार 26 किस्तें समय पर जमा कीं। नवंबर 2025 तक का भुगतान बैंक रिकॉर्ड में दर्ज है। दिसंबर 2025 में तकनीकी समस्या के कारण बैंक से किस्त नहीं कट पाई, जिसके बाद रिक्वरी एजेंट कुलदीप शर्मा और सुनील वर्मा ने घर आकर दिसंबर और जनवरी की किस्त का भुगतान नकद (Cash) लिया। आरोप है कि सिस्टम खराब होने का बहाना बनाकर एजेंटों ने इसकी रसीद नहीं दी।

बीच सड़क पर गुंडागर्दी और अभद्रता

धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब बैंक से बकाया होने का कॉल आया। जब किशोर पंवार ने एजेंटों से रसीद मांगी, तो वे टालमटोल करने लगे। लगभग एक महीने पहले, जब किशोर पंवार अपने परिवार और मेहमानों के साथ कार से जा रहे थे, तभी परमाणु नगर के पास कुलदीप और सुनील के भेजे गए गुंडों ने कार को घेर लिया। पीड़ित का आरोप है कि:

बिना किसी कानूनी नोटिस या सूचना के कार को बीच रास्ते रोका गया। गुंडों ने परिवार के सदस्यों और महिलाओं के साथ गाली-गलौज व हाथापाई की। पीड़ित को अपमानित कर जबरन कार छीन ली गई और एजेंट फरार हो गए।

पुलिस और बैंक प्रशासन की चुप्पी पीड़ित जब बैंक कार्यालय पहुंचे, तो वहां उन्हें सहायता देने के बजाय धमकाया गया। वहीं, कानून की रक्षा करने वाली पुलिस का रवैया भी निराशाजनक रहा। पीड़ित का कहना है कि वे राजेंद्र नगर थाने के तीन चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बड़ा सवाल: RBI के स्पष्ट निर्देश हैं कि रिक्वरी के लिए किसी भी ग्राहक के साथ शारीरिक बल या अभद्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंदौर में बैंक एजेंटों को कानून का कोई खोफ नहीं है? क्या प्रशासन इन दबंग एजेंटों पर लगाम लगाएगा या पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर भटकता रहेगा?

संयुक्त संचालक शिक्षा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की



शहडोल संयुक्त संचालक लोक शिक्षण शहडोल संभाग श्री उमेश कुमार धुर्वे ने शहडोल संभाग के शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं प्राचार्यों की बैठक भारत माता उ.मा.वि. शहडोल के सभागार में ली।

उन्होंने समेकित छात्रवृत्ति, एमपी टास छात्रवृत्ति, बेहतर परीक्षा परिणाम, परीक्षा के पूर्व परीक्षा केन्द्रों में साफ-सफाई, विद्युत् डेस्क

में बैठक व्यवस्था, शिक्षकों की ई-अटेंडेंस, विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति, अपार आईडी, परीक्षा पर चर्चा एवं अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर यथाशीघ्र शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री फूल सिंह मरपाची, सहायक संचालक श्री आरके मंगलानी, एपीसी रमसा श्री अरविंद पाण्डेय एवं विद्यालय के प्राचार्य उपस्थित रहे।

भोजशाला में नमाज भी होगी और पूजा भी.. सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर लंबे वक्त से चले आ रहे विवाद में एक नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने बसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती पूजा और नमाज पढ़ने के लिए दोनों पक्षों के एक साथ स्थान साझा करने की मंजूरी दी है। कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमा नमाज अदा करने की इजाजत दी है। साथ ही प्रशासन से परिसर में बैरिकेडिंग और अलग-अलग प्रवेश-निकास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। दरअसल, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर की गई याचिका में आगामी वसंत पंचमी (23 जनवरी 2026, शुक्रवार) को भोजशाला में केवल हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की अनुमति देने और मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने से रोकने की मांग की है। वहीं, सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया, ताकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो सके।

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर की गई याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच सुनवाई कर रही है। इस याचिका में हिंदू संगठन ने भोजशाला को हिंदू मंदिर मानते हुए सरस्वती पूजा के लिए विशेष अनुमति की मांगी है कोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कहा कि मुख्य याचिका पहले ही अप्रभावी हो चुकी है और ये आवेदन एक लंबित मामले में दायर किया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि पहले की व्यवस्थाओं के अनुसार कानून-व्यवस्था के इंतजाम किए जा सकते हैं। दूसरी ओर मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने दलील दी कि पहले भी तीन बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने हिंदू पक्ष को तीन घंटे तक पूजा की अनुमति दी है। उन्होंने कहा, "ऐसा ही दोबारा होने दिया जाए। जुमा की नमाज दोपहर एक से तीन बजे तक होती है।"

एनसीसी कैडेट को स्कूल बस ने कचला मौके पर ही मौत



भिंड शहर की अटेर रोड पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 17 वर्षीय एनसीसी कैडेट की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस लाइन में परेड रिहर्सल के लिए ऑटो का इंतजार कर रहे छात्र को तेज रफ्तार स्कूल बस ने टक्कर मार दी टक्कर के बाद छात्र सड़क पर गिर पड़ा और बस का पिछला पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई हादसा दोपहर करीब 12:30 बजे चंदनपुरा गांव के पास हुआ मृतक की पहचान मिश्रन का पूरा निवासी बृजेंद्र जाटव के पुत्र प्रिंस जाटव 17 वर्ष के रूप में हुई है। प्रिंस 12वीं कक्षा का छात्र था। और गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड की रिहर्सल में शामिल होने जा रहा था। वह एनसीसी

का सक्रिय क्रेडिट था। प्रत्यक्ष दर्शी के अनुसार प्रिंस सड़क किनारे खड़ा होकर ऑटो का इंतजार कर रहा था तभी अटेर रोड की ओर से तेज गति से आ रही आईपीएस स्कूल की बस ने उसे टक्कर मार दी। आक्रोश में बदला मातम सड़क पर बैठी महिलाएं दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों में गुस्सा फूट पड़ा महिलाओं ने रोड पर बैठकर 1 घंटे तक जाम लगाया लोगों ने आरोपी बस चालक की तत्काल गिरफ्तारी पीड़ित परिवार को मुआयजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। सूचना मिलने पर देहात थाना टीआई मुकेश शाक्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे ने आरोपी बस चालक की गिरफ्तारी की जानकारी दी इसके बाद प्रदर्शन शांत हुआ और जाम हटाया गया।

बजट 2026 से रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत की उम्मीद, होम लोन ब्याज छूट 5 लाख करने और उद्योग का दर्जा देने की मांग

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026 से पहले रियल एस्टेट सेक्टर ने सरकार के सामने अपनी मांगों की लंबी सूची रख दी है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी नारेडको ने साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा आर्थिक हालात और बढ़ती आवास लागत को देखते हुए होम लोन पर ब्याज में मिलने वाली आयकर छूट की सीमा को मौजूदा दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाना चाहिए। नारेडको का मानना है कि इससे न सिर्फ मध्यम वर्ग और पहली बार घर खरीदने वालों को राहत मिलेगी, बल्कि आवास क्षेत्र में मांग भी तेज होगी, जो पिछले कुछ वर्षों से दबाव में है। नारेडको ने यह मांग उस समय रखी है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने जा रही हैं। संगठन का कहना है कि पिछले 12 वर्षों से होम लोन ब्याज पर कर छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि इस दौरान प्रॉपर्टी की कीमतें, निर्माण लागत और कर्ज की दरें काफी बढ़ चुकी हैं। ऐसे में दो लाख रुपये की सीमा अब अप्रासंगिक हो गई है और इसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये करना समय की जरूरत बन गया है। नारेडको के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि बढ़ती ब्याज दरों और महंगे घरों के दौर में होम लोन लेने वाले खरीदारों पर वित्तीय बोझ लगातार बढ़ रहा है। यदि सरकार ब्याज छूट की

सीमा बढ़ाती है तो इससे घर खरीदने का फैसला आसान होगा और रियल एस्टेट बाजार में नई जान आएगी। उन्होंने कहा कि आवास क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इससे जुड़े फैसलों का सीधा असर रोजगार, उपभोग और शहरी विकास पर पड़ता है। होम लोन ब्याज छूट के अलावा नारेडको ने किफायती आवास की परिभाषा में बदलाव की भी जोरदार मांग की है। संगठन का कहना है कि मौजूदा समय में किफायती आवास की सीमा 45 लाख रुपये तय है, जो बड़े शहरों और तेजी से बढ़ते शहरी इलाकों के लिहाज से अब व्यावहारिक नहीं रही है। नारेडको का सुझाव है कि 90 लाख रुपये तक की कीमत वाले घरों को किफायती आवास की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। इससे ज्यादा लोगों को सस्ते जीएसटी और अन्य कर लाभ मिल सकेंगे और किफायती आवास योजनाओं को भी गति मिलेगी। नारेडको का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में जमीन की कीमत, निर्माण सामग्री और मजदूरी लागत में भारी इजाफा हुआ है। ऐसे में 45 लाख रुपये की सीमा में गुणवत्तापूर्ण घर बनाना कई शहरों में संभव नहीं रह गया है। यदि सरकार परिभाषा में बदलाव करती है तो डेवलपर्स को भी राहत मिलेगी और वे मध्यम आय वर्ग के लिए ज्यादा आवास परियोजनाएं शुरू कर पाएंगे। नारेडको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने

कहा कि केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन किफायती आवास के मोर्चे पर अभी और काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है और इसके लिए आवास को अन्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के समान महत्व दिया जाना चाहिए। हीरानंदानी ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को अपने पास पड़ी खाली जमीनों का बेहतर उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई शहरी इलाकों में केंद्र और राज्य सरकारों के पास बड़ी मात्रा में जमीन खाली पड़ी है, जिसका उपयोग किफायती और मध्यम आय वर्ग के आवास निर्माण के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल अपनाया जा सकता है, जिससे निजी क्षेत्र की दक्षता और सरकारी संसाधनों का बेहतर तालमेल बनेगा। नारेडको ने किराये के आवास को बढ़ावा देने की मांग भी बजट 2026 के एजेंडे में शामिल की है। संगठन का कहना है कि मौजूदा समय में किराये से मिलने वाला रिटर्न बेहद कम है, जो आमतौर पर एक से तीन प्रतिशत के बीच रहता है। इतनी कम आय के चलते रियल एस्टेट कंपनियों के लिए किराये के मकान बनाना और उन्हें लंबे समय तक संचालित करना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रह जाता।

कबाड़ से कमाई का सुनहरा मौका हाथ से निकल रहा है

नीति आयोग की रिपोर्ट ने खोली भारत की रीसाइक्लिंग व्यवस्था की कमजोरियां

नई दिल्ली। भारत में तेजी से बढ़ते कचरे और कबाड़ से जुड़ा रीसाइक्लिंग कारोबार आने वाले वर्षों में अरबों रुपये का अवसर बन सकता है, लेकिन नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने इस क्षेत्र की हकीकत उजागर कर दी है। आयोग के अनुसार, असंगठित स्कैप रीसाइक्लिंग, कमजोर प्रसंस्करण क्षमता और व्यापक अक्षमताओं के कारण भारत हजारों करोड़ रुपये के संभावित रीसाइक्लिंग बिजनेस से वंचित हो रहा है। यह स्थिति तब है, जब देश में ई-कचरा, बेकार टायर, लिथियम-आयन बैटरी और एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है। नीति आयोग ने अलग-अलग रिपोर्टों के जरिए भारत के रीसाइक्लिंग उद्योग की वास्तविक क्षमता और चुनौतियों का आकलन किया है। इन रिपोर्टों में साफ तौर पर कहा गया है कि यदि मौजूदा व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया, तो देश न केवल आर्थिक अवसर गंवाता रहेगा, बल्कि पर्यावरणीय संकट भी गहराता जाएगा। आयोग का मानना है कि सर्कुलर इकोनॉमी यानी संसाधनों के अधिकतम और टिकाऊ उपयोग की दिशा में रीसाइक्लिंग सबसे अहम कड़ी

है, लेकिन भारत अभी इस रास्ते पर बहुत पीछे है। ई-कचरे को लेकर रिपोर्ट में सबसे चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। नीति आयोग के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का कुल प्रवाह लगभग 51 हजार करोड़ रुपये का है, जिसमें से करीब 60 प्रतिशत मूल्यवान सामग्री निकाली जा सकती है। इसके बावजूद मौजूदा रिकवरी सिस्टम केवल 18 प्रतिशत ई-कचरे से ही उपयोगी संसाधन निकाल पा रहा है। इसका मतलब यह है कि बड़ी मात्रा में कीमती धातुएं, कंपोनेंट्स और अन्य संसाधन या तो बेकार जा रहे हैं या फिर बेहद असुरक्षित और गैर-वैज्ञानिक तरीके से नष्ट हो रहे हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत सालाना करीब 62 लाख टन ई-कचरा पैदा करता है और यह आंकड़ा 2030 तक बढ़कर लगभग 1.4 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान है। इसके मुकाबले देश की औपचारिक रीसाइक्लिंग क्षमता करीब 20 लाख टन तक ही सीमित है। सबसे गंभीर बात यह है कि कुल ई-कचरे का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा ही अधिकृत और संगठित चैनलों के माध्यम

से रीसाइक्लिंग के लिए पहुंच पाता है, जबकि शेष हिस्सा असंगठित क्षेत्र में चला जाता है, जहां पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरे पैदा होते हैं। नीति आयोग का कहना है कि असंगठित क्षेत्र में रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया बेहद अवैज्ञानिक होती है। इसमें न तो सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है और न ही संसाधनों की पूर्ण रिकवरी हो पाती है। नतीजतन, न सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है बल्कि प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ते हैं। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि इस क्षेत्र को औपचारिक ढांचे में नहीं लाया गया, तो भारत सर्कुलर इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा।

बेकार टायरों की रीसाइक्लिंग को लेकर भी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। नीति आयोग के अनुसार, रीसाइक्लिंग किए गए टायर उत्पादों के लिए स्पष्ट गुणवत्ता मानकों की कमी के कारण देश को करीब 7,500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। बिना मानकों के रीसाइक्लिंग से उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं, जिससे इनका उपयोग सीमित रह जाता है और बाजार में इनकी मांग नहीं बन

पाती। इसका सीधा असर इस पूरे सेक्टर की आर्थिक व्यवहार्यता पर पड़ता है। रिपोर्ट में लिथियम-आयन बैटरियों और बेकार हो चुके वाहनों की रीसाइक्लिंग को भी भविष्य के बड़े अवसर के रूप में देखा गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ लिथियम-आयन बैटरियों का कचरा आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ने वाला है। यदि समय रहते मजबूत रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम तैयार नहीं किया गया, तो यह कचरा एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या में बदल सकता है। वहीं, सही नीति और तकनीक के जरिए यही कचरा बहुमूल्य धातुओं का बड़ा स्रोत भी बन सकता है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया है कि भारत में रीसाइक्लिंग सेक्टर के सामने सिर्फ तकनीकी ही नहीं, बल्कि संस्थागत और मानव संसाधन से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। कमजोर कार्यबल प्रणालियां, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और गुणवत्ता मानकों का अभाव इस उद्योग की प्रगति में बड़ी बाधा बने हुए हैं। आयोग के कार्यक्रम प्रमुख प्रियव्रत भाटी द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है।

गांधी टॉक्स में काम करना चुनौतीपूर्ण और रोमांचक

अभिनेत्री अदिति राव हैदरी अपनी अपकमिंग साइलेंट फिल्म 'गांधी टॉक्स' की रिलीज को लेकर उत्साहित हैं। इस बीच उन्होंने बताया कि फिल्म में काम करने का अनुभव चुनौतीपूर्ण और रोमांचक दोनों रहा। उन्होंने फिल्म में विजय सेतुपति के साथ स्क्रीन शेयर करने के अनुभव को शानदार बताया। किशोर पांडुरंग बेल्लेकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अदिति ने कहा कि यह उनके लिए पहली बार विजय सेतुपति के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। हालांकि पहले भी कई प्रोजेक्ट्स में दोनों साथ आने वाले थे, लेकिन किसी न किसी कारण से वे पूरे नहीं हो पाए। अदिति ने बताया, हम कुछ फिल्मों में लगभग साथ काम करने वाले थे, लेकिन हर बार कुछ न कुछ हो गया और बात आगे नहीं बढ़ पाई। यह जिंक्स टूटना ही था। मुझे खुशी है कि ये एक बहुत अलग और खास फिल्म 'गांधी टॉक्स' के साथ पूरा हुआ।

उन्होंने इस फिल्म को अपनी जिंदगी के सबसे अनोखे प्रोजेक्ट में से एक करार दिया। फिल्म पूरी तरह साइलेंट है, जिसमें कोई डायलॉग नहीं हैं। अदिति ने कहा, इस फिल्म में आप बस शांत रहते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। बिना डायलॉग के भी भावनाएं जाहिर करनी होती हैं, यही इसकी खूबसूरती है। यह मेरे लिए जितना चुनौतीपूर्ण था, उतनी ही रोमांचक भी। अदिति हमेशा गहरे, सच्चे और अर्थपूर्ण किरदारों वाली कहानियां चुनती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर का पांच साल का बच्चा आज भी जिंदा है, जो सपने देखता है, उन पर भरोसा करता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। यही सकारात्मक सोच उन्हें सही स्क्रिप्ट्स और निर्देशकों का इंतजार करने की ताकत देती है। उन्होंने कहा, मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स अक्सर नहीं मिलतीं, लेकिन मैं उनका इंतजार करती हूं और उन निर्देशकों का भी, जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूं। मैं शिकायत नहीं करती, क्योंकि वो मौके आखिरकार आते ही हैं। फिल्म में अदिति राव हैदरी के साथ विजय



सेतुपति, अरविंद स्वामी और सिद्धार्थ जाधव मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि फिल्म के संगीत को एआर रहमान ने तैयार किया है। फिल्म 30 जनवरी को रिलीज होगी। 'गांधी टॉक्स' के अलावा अदिति की एक और रोमांचक प्रोजेक्ट इम्तियाज अली की 'ओ साथी रे' है, जो एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है। इसमें उनके साथ अर्जुन रामपाल और अविनाश तिवारी नजर आएंगे। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर आने वाली है और समकालीन समय में पुरानी भावनाओं वाले प्यार की कहानी कहती है।

बसंत पंचमी विशेष'

सभी सृजनात्मक कार्य साक्षात् मां शारदा का ही आशीर्वाद हैं

सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवताम्।

देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः॥

अर्थात्- वाणी की अधिष्ठात्री उन देवी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मनुष्य देवता बन जाता है। बसंत पंचमी का भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्व है। यह अवसर मां शारदे के प्राकट्य दिवस के रूप में विशेष महत्व रखता है। मां सरस्वती की आराधना उत्पादकता, सृजनात्मकता, कलात्मकता व बुद्धिमत्ता को प्रदान करने वाली होती है। समस्त प्रकार की विद्याएं व कलाएं मां के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती हैं। कलाओं को ललित कला तथा उपयोगी कला में विभाजित किया गया है। संगीत, नृत्य, काव्य, चित्र, वास्तुकला आदि ललित कला के अन्तर्गत आते हैं जबकि कृषि, लुहार, सुनार, पाक-कला आदि उपयोगी कलाओं के रूप में जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में इन कलाओं का विधिवत प्रशिक्षण दिया जाता था। हमारे ग्रंथों में चौंसठ सृजनात्मक कलाओं का उल्लेख है। वर्तमान में



भौतिकतावादी दृष्टिकोण के चलते कम उम्र से ही बच्चे एक अनावश्यक प्रतियोगिता का हिस्सा बना

दिए जाते हैं। ऐसे में उनमें सृजनात्मक कलाओं के विकास की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। किसी भी विद्या या कला को पाने का आज का मुख्य उद्देश्य अधिकांशतः प्रसिद्धि अथवा धन की प्राप्ति ही होता है। यही कारण है कि न तो विद्या व न ही कला में व्यक्ति उत्कृष्टता को प्राप्त कर पाता है। इस संदर्भ में सहजयोग प्रणेता परम पूज्य श्री माताजी हमें दिग्दर्शित करती हैं कि,

यह सृजनशक्ति सरस्वती का आशीर्वाद है जिसके द्वारा अनेक कलाएं अल्पत्र हुई... कला की और दृष्टि बढ़ाने से एक तो जीवन में सौन्दर्य आ जाता है और जीवन का रहन-सहन सुन्दर हो जाता है... हमारे ऊबड़ खाबड़ जीवन में यदि थोड़ी सी कला की झलक आ जाए तो बड़ा सुख और आनंद मिलता है। परंतु अगर आप कला को बगैर आत्मसाक्षात्कार के ही अपनाना चाहें तो वह कला अधूरी रह जाती है ... अगर आत्मसाक्षात्कारी मनुष्य ... कोई कलात्मक चीज बनाता है तो उसमें से भी चैतन्य आने लग जाता है। सुन्दर होने के साथ साथ

ऐसी कृति में एक तरह की अनन्त शक्ति होती है... क्योंकि उसने जो कुछ भी बनाया है आत्मा की अनुभूति से बनाया है। ... हाथ से बनी हुई चीजों में चैतन्य बहता है।... हाथ से बनी चीजों के द्वारा अपने हृदय का आनंद हम दूसरों को समर्पित करते हैं। ... कलात्मक चीज हठात् आपको निर्विचारिता में उतारेगी ... क्योंकि सौन्दर्य देखने से ही चैतन्य एक दम बहने लगता है। कला का जो भी कार्य हम करते हैं वह परमात्मा को समर्पित होना चाहिए। इस भाव से की गई सभी रचनाएं शाश्वत होंगी। परमात्मा को समर्पित सभी कविताएं, संगीत और कलाकृतियां आज भी जीवित हैं।... कला परमात्मा की ज्योति है... इनमें चैतन्य लहरियां हैं। इस बसंत पंचमी श्री माताजी के दिव्य आशीर्वाद की छत्रछाया को प्राप्त करने हेतु सहजयोग से संबंधित जानकारी निम्न साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। यह पूर्णतया निशुल्क है। टोल फ्री नं - 1800 2700 800 अथवा यूट्यूब चैनल लर्निंग सहजयोगा से प्राप्त कर सकते हैं।

AI की दुनिया में भारत की ऊंची छलांग, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ग्लोबल प्लान

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा के दौरान भारत के पांच-स्तरीय एआई मिशन की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने भारत के महत्वाकांक्षी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के पांच मुख्य आधारों- अनुप्रयोग, मॉडल, चिप, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा—पर प्रकाश डाला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व आर्थिक मंच पर बोलते हुए यह स्पष्ट किया कि भारत केवल तकनीक का उपयोग ही नहीं कर रहा, बल्कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और क्वालिटी कंयूटिंग क्षमता के जरिए इस 'पांचवीं औद्योगिक क्रांति' का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।

एआई के पांच आधार

तकनीकी ढांचे को समझाते के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को देखें, तो इसके पांच आधार हैं। पहला तत्व अनुप्रयोग परत है, यानी हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। दूसरा तत्व मॉडल परत है, यानी बनाए गए मॉडल, तीसरा तत्व चिप परत है, यानी अर्धचालक परत, चौथा तत्व अवसंरचना परत है, यानी डेटा केंद्र और पांचवां तत्व ऊर्जा है। उन्होंने आगे कहा कि पांचवीं औद्योगिक क्रांति कहलाने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में ऊर्जा एक बहुत बड़ा कारक बनने जा रही है। इस तरह की स्थिति में, ऊर्जा से लेकर अनुप्रयोगों तक, भारत के व्यवस्थित कार्य की दुनिया भर में और विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित उद्योग द्वारा बहुत सराहना की गई है। इसी बीच, अश्विनी वैष्णव ने वैश्विक कृत्रिम



बुद्धिमत्ता परिदृश्य पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भारत की व्यापक रणनीति का विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा नियंत्रित संसाधनों से हटकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल की ओर बदलाव पर जोर

दिया गया है।

भारत की भागीदारी

विश्व आर्थिक मंच पर आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभाव में एआई की भूमिका पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने खुलासा किया कि भारत ने

38,000 जीपीयू के साथ एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी को एक साझा कंप्यूटिंग सुविधा के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है, यह छात्रों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक लागत के लगभग एक तिहाई पर उपलब्ध है, जबकि कई देशों में बड़ी टेक कंपनियां जीपीयू तक पहुंच को नियंत्रित करती हैं।

नियमन के मुद्दे को लेकर कही ये बात

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने केवल स्वतंत्र कानून पर निर्भर रहने के बजाय तकनीकी-कानूनी दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि आधुनिक प्रौद्योगिकी की जटिलताओं के लिए पूर्वाग्रह और डीपफेक जैसे जोखिमों से निपटने के लिए मजबूत तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता है, जिनमें न्यायिक जांच में खरे उतरने के लिए पर्याप्त सटीक पहचान प्रणाली शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत पूर्वाग्रह को कम करने, विश्वसनीय डीपफेक पहचान को सक्षम बनाने और एआई मॉडल को तैनात करने से पहले उचित अनलर्निंग सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहा है। उन्होंने पांचवीं औद्योगिक क्रांति की अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक बदलाव पर भी प्रकाश डाला, और सुझाव दिया कि भविष्य में भारी मात्रा में निवेश पर लाभ (आरओआई) केवल "ब्रूट-फोर्स" कंप्यूटिंग के बजाय लागत प्रभावी, स्केलेबल समाधानों से आएगा। इस दौरान उन्होंने इस मिथक को खारिज किया कि एआई की सभी प्रगति के लिए महंगे हार्डवेयर की आवश्यकता होती है और कहा कि लगभग 95 प्रतिशत एआई कार्य 20-50 बिलियन पैरामीटर मॉडल का उपयोग करके किया जा सकता है।